



VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1391)

Name of Candidate	SUNIL KUMAR		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	729226
Center	Jaipur	Date	25/11/2019

INDEX TABLE			INSTRUCTIONS
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained	
1	12.5		1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code). उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)। 2. There are TWENTY questions printed in ENGLISH & HINDI इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं। 3. All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए। 7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।
2	12.5		
3	12.5		
4	12.5		
5	12.5		
6	12.5		
7	12.5		
8	12.5		
9	12.5		
10	12.5		
11	12.5		
12	12.5		
13	12.5		
14	12.5		
15	12.5		
16	12.5		
17	12.5		
18	12.5		
19	12.5		
20	12.5		
Total Marks Obtained:			
Remarks:			

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. Enumerate important privileges enjoyed by each House of Parliament collectively and its members individually and also discuss their significance.
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्व की भी चर्चा कीजिए।

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों व अनु 194 में विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है।

सामूहिक विशेषाधिकार -

- ★ सदन में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई बात पर व्यापार में कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
- ★ सदन के दौरान किसी भी सदस्य को सदन के अध्यक्ष / सभापति की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- ★ सदन अपनी कार्यवाही अपने अनुसार कर सकता है। गुप्त बैठक कर सकता है। कार्यवाही का प्रमाण ले सकता है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

- * 'सदन के सदस्य को लग के दौरान न्यायालय में उपस्थित हेतु मजबूर नहीं' किया जा सकता है।
- * संसद सदस्य को भेगी सरा बालत जानकारी नहीं' दी जा सकती है।
- * सदन में बोलने व बयान पर न्यायालय में' प्रहनयिधन नहीं' लगाया जा सकता है।

महत्व - संसदीय विशेषाधिकार जनप्रतिनिधियों

के जनता की आवाज बनने में सहायक हैं। इससे कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित होता है। सामूहिक अधिकारों से लोकतंत्र के तैरिए संसद की गरिमा बनी रहती है। संपद निरुद्ध होकर कार्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष - स्पष्ट है कि विशेषाधिकार उत्तरदायी लोकतंत्र की पूर्णता है लेकिन इनको पूर्णतः किमा जाना भी आवश्यक है।

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

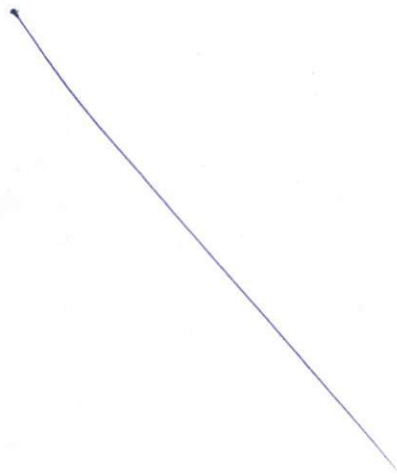
12.5X20=250

1. Enumerate important privileges enjoyed by each House of Parliament collectively and its members individually and also discuss their significance.
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्व की भी चर्चा कीजिए।

1391

VISION IAS™

Don't write
anything this
margin
(इस भाग में
कुछ ना लिखें)



2. Give an account of the composition and functions of the Finance Commission as mentioned in the Constitution of India.

भारत के संविधान में यथा उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण दीजिए।

संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है।

संरचना - वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

शैक्षणता - अध्यक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।

सदस्य -

- * अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो
- * लेखाशास्त्र के विशेषज्ञ हो
- * पार्वजनिक अनुभव रखने वाले हो

अध्यक्ष व सदस्यों की आयु, सेवाशर्तों आदि के बारे में संविधान मौन है। प्रत्येक 5 वर्ष से केन्द्र - राज्य राजस्व विभाग व निर्दिष्ट मुद्दों हेतु इसका गठन होता है।

कार्य - वित्त आयोग के निम्न कार्य हैं-

- * केन्द्र - राज्य के मध्य शुद्ध राजस्व का बितरण का अनुपात एवं करना
- * पंचायती राज संस्थाओं के कविर वितीयन हेतु वित्त की व्यवस्था करना
- * राजकोषीय संघनाद की मजबूती हेतु सुझाव
- * राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामले ।

हाल ही में 15 वां वित्त आयोग का गठन किया गया है जो अपने सुझावों में 2011 की जनगणना के आंकड़े शामिल करने पर विचार कर रहा है जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध हो रहा है।

निष्कर्ष :- वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है इसे सहकारी व उतित्वपूर्ण संघनाद के लिए द्वितीय उपायनिक सुधार आयोग के सुझावों पर अमल का मजबूत बनाना चाहिए





3. Preamble shows the general purposes behind several provisions in the Constitution, and is a key to the minds of the makers of the Constitution. Explain. Also, comment on the amendability of the Preamble.

उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है और संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए। साथ ही, उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए।

संविधान सभा में 11 नवम्बर 1946 को
नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव का
परिष्कृत रूप बाद में उद्देशिका बनी।

उद्देशिका में समस्त संविधान
का निचोड़ समाया हुआ है जिसे निम्न
बिंदुओं से समझा जा सकता है -

* हम भारत के लोग - यह लोकप्रमुख
को दर्शाता है जो हमारे पंचायती राज (243)
से लेकर संसद तक आम जन की आवाज
के उत्तरदायित्व पूर्ण प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

* लोकतान्त्रिक समाजवाद - भारत ने समाजवाद
का लोकतान्त्रिक ढाँडा अपनाया है जिसे मौलिक
अधिकारों में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में
तथा नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38, 39,
41, 42, 43 में सहज ही देखा जा
सकता है।

सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय :-

मूल अधिकार (अनु० 12-35) तथा नीति निर्देशक
तत्वों (अनु० 36-51) एक इसी दर्शन को
चिन्ता से वर्णित किया गया है।

उदा० - अनु० 17 अल्पसंख्यकों का अधिकार - सामाजिक न्याय

अनु० 39(1, E) धन का संकेन्द्रण नहीं - आर्थिक न्याय

अनु० 14, 15 - अवसर की समानता > राजनीतिक
326 - प्रत्यक्ष अधिकार न्याय

स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व - मूल अधिकारों
व DPSP में इसी को व्याख्याति किया है।

धर्मनिरपेक्षता - अनु० 15 - धर्म के आधार पर
विभेद का प्रतिषेध

अनु० 25, 26, 27, 28 धार्मिक मामलों की
स्वतंत्रता इसके अंतर्गत को शामिल है।

स्पष्ट है कि प्रस्तावना संघीय संविधान की
कुंजी है।

संशोधन :- प्रस्तावना में संशोधन संबंधी
मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के सामने बार-बार
उठा है। जिसे केशवानन्द भारती वाद 1973

में स्पष्ट बताया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसे मूल दोनो भागों 'बर्खास्त' या 'कटा' है। 42 के संविधान संशोधन 1976 में इसमें समाजवाद, पंचनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े थे जिसे न्यायालय ने खारिज माना।

निष्कर्ष:- डा. भीमपव अंबेडकर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है।

4. Explain the principle of subsidiarity, its importance and discuss how the 73rd constitutional amendment act tries to achieve it.

समनुषंगिता के सिद्धांत व इसके महत्व की व्याख्या कीजिए एवं चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है।

भारत में लोकतांत्रिक संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें शासन के तीन स्तर केन्द्र, राज्य व स्थानीय स्वशासन हैं।

समनुषंगिता - संविधान में विकेन्द्रीकरण व उत्तरदायी शासन पर अव्यक्तिक बल दिया गया है। अनु० ५० भी ग्राम पंचायतों की स्थापना हेतु निर्देशित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार शासन के विभिन्न अंग होने चाहिए जो क्रमशः आपस में केन्द्रित हों।

महत्व - भारत में आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली नहीं है जिसे आधारभूत स्तर तक पहुँचाने के लिए स्थानीय स्वशासन का सहारा लेना आवश्यक है। यद्यपि भारत में बोलचाल से ही ग्राम स्वशासन के अभाव मिलते हैं लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे समनुषंगिता के सिद्धांत के तहत स्थापित किया है जो आज के विकेन्द्रीकृत व पारदर्शी शासन का कारण बन रहा है।

73 वां संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ जिसमें पंचायती राज को संविधान में स्थान दिया गया। इसमें अनुच्छेद 9 व अनुच्छेद 243 को जोड़ा।

इस प्रावधान के बाद पंचायती राज में विलीयन, निश्चित युग, अफसरशाली का स्भाव जैसी लक्षणाएँ हर हुई तथा पंचायती राज मजबूत हुआ है। महिला उपनिधियों की कड़ी सेव्या इसका मुख्य फल है।

यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों ने पंचायती राज को सभी 29 विषय हस्तांतरित नहीं किए हैं तथा पुरुष प्रधानता व जातिवाद का अभाव इसमें बाधक बने हुए हैं। किंतु इस संविधान संशोधन ने शासन के इस तीसरे स्तर को मजबूती जरूर प्रदान की है।

5. Explaining the importance of an independent judiciary, highlight the relevant Constitutional provisions that safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court.

एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।

भारत में शास्त्रिय प्रयुक्त लिखित के अनुसार शासन के अंगों को अलग व स्वतंत्र बनाया है यद्यपि ये सब व बेलेंस की व्यवस्था जरूर की है।

स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व

- 1. लोकतंत्र में संविधान के अनुसार शासन की उपयुक्त व्यवस्था स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है।
- 2. कार्यपालिका की गानाशाही से न्यायपालिका ही रक्षा कर सकती है।
- 3. नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक।
- 4. संविधान की रक्षा हेतु आवश्यक।
- 5. संघीय ढांचे को बचाने के लिए आवश्यक।
Ex. हाल ही में महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार ने राज्यपाल को एजेण्ट की भूमिका इस्तेमाल कर राज्य सरकार में हस्तक्षेप किया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
2019 में व्याख्या यह स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना संभव नहीं है।

संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका हेतु ^{निम्न} उपबन्धन
किए हैं -

- * अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत
विधि को शून्य घोषित करने की
शक्ति न्यायपालिका को देगा है।
- * अनुच्छेद 226 ऐसी ही शक्ति उच्च
न्यायालयों को देगा है।
- * अनुच्छेद 32 नागरिकों की मूल अधिकारों
की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय को
रिट हेतु अधिकार देगा है।
- * अनु. 124 व 213 अनिलेख न्यायालय
व अवमानना के उपबन्धन उल्लेखित
करेगा है।
- * न्यायाधीशों की नियुक्ति, हटाना, सेवा शर्तों संबंधी स्वेच्छा
स्पष्ट है कि भारत में संविधान
की तर्ज पर हैं जिसकी व्याख्या का अंतिम
अधिकार न्यायपालिका का पास है अतः
न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अप्रत्याशित है।

जिसे सेविदान ने जली अति इल्लेख भी
किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. प्रसाद न्यायी
वर्ष 1973 व NJAC 2015 में भी
न्यायिक परीक्षण व स्वतंत्र न्यायपालिका को
मूल हक मानते हुए अनुसूची में शामिल है।

6. Mention the six freedoms as guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution. Also, comment on the way in which the constitution has attempted to strike a balance between individual liberty and interests of society.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत छः स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही, संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए।

संविधान के भाग 3 में अनु. 19 में निम्न 6 स्वतंत्रताएँ उल्लिखित हैं -

1. विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. शांतिपूर्वक सभ्यताओं की स्वतंत्रता
3. संधि बनाने व शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता
4. भारत में कहीं भी संचरण की स्वतंत्रता
5. भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता
6. भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता

अर्थात् अनुच्छेद 19(2) में उपर्युक्त स्वतंत्रताओं पर सुव्यवस्थित निर्बंधन भी आरोपित किए हैं ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित हो सके।

निर्बंधन - * विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा व अखण्डता, निली इतरे की भावनाओं के ठेस पहुंचाने आदि संदर्भ में प्रतिबंधित किया जा सकता है।

* सम्मेलन करने व लेख बनाने की स्वतंत्रता को द्रोहि भेग करने, कानून व व्यवस्था बिगाड़ने राष्ट्रीय रक्षा व अखण्डता के संदर्भ में रोक जा सकता है।

* विचारण करने व बनाने की स्वतंत्रता को वेश्या छवि वाली महिला, अपराधी व्यक्ति आदि के संदर्भ में प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

स्पष्ट है कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता

नहीं है। यानी को स्वतंत्रता देने के लिए व्यक्ति व समाज के मध्य संतुलन कायम रखना होगा जिसे सत्त-सत्त पर सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है जैसे IT Act 2008 की धारा 66A विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक प्रतिबंध लगाती थी जिसे न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया।

1391

VISION IASTM

Don't write
anything this
margin
(इस आध में
कुछ ना लिखें)

7. With examples, discuss the significance of alternative dispute resolution mechanisms in light of costly and time-consuming litigation process in India.

भारत में महंगी और समयसाध्य वाद प्रक्रिया के आलोक में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

न्याय में देरी, अन्याय के समान है, कृष्ण
भारत में चरितार्थ हो रही है। भारत में
न्यायालयों में 4 करोड़ से अधिक वाद लंबित हैं।

महंगी - भारत में न्यायिक प्रक्रिया अटिल
व आम जन से सहज नहीं है। उसकी भाषा,
नियम व प्रक्रिया विलुप्त है अतः वकीलों
का सहाय लेना पड़ता है जिसे 30 करोड़ से
अधिक BPL जैसे भारतीय सहन नहीं कर
सकते हैं। अतः वैकल्पिक विवाद समाधान
को अपनाया होगा।

वैकल्पिक विवाद समाधान :- अनुच्छेद 45

में भी निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान
किया गया है। इसी क्रम में 1987 में
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया
यह समाधान तंत्र लोक अदालतों, पारिवारिक अदालतों
व ग्राम न्यायालयों के तहत चलता व स्वयं
न्याय दिलाने हेतु प्रतिकूल है।

लोक अदालत - यह स्थानीय विवादों को महत्वपूर्णता से निपटाने पर बल देती है। अगली रक यह लाखों विवाद निपटार करती है इनमें प्रक्रिया लंबितियों का पालन नहीं किया जाता है। तथा इसका निर्णय अंतिम होता है जिससे समय बच निकलता है।

पारिवारिक अदालत - पारिवारिक विवादों जैसे पति - पत्नी के झगड़ों का विवाद आदि को न्यायपालिका में लड़कर वकीलों से नहीं सुलझाया जा सकता है अतः यह कैबलिंग तंत्र उन्हें आपस में सुलह के लिए रास्ता कर धन व समय बचाता है।

ग्राम न्यायालय - 2008 से शुरू यह जगती ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के सिविल व जैववारी मामलों का निपटार करती है इसमें जिला न्यायाधीश के स्तर का न्यायाधीश न्याय करता है अन्य सदस्य सार्वजनिक अनुभव रखते हैं।

अधिकरण - अनु 323 में A (अधिकारी), B (अधीनस्थ अधिकारी) का उल्लेख है जो सिविल मामलों को जल्दी निपटारते हैं जैसे राष्ट्रीय हरि न्यायाधिकरण

निष्कर्ष - स्पष्ट है कि भारत में मछली व समुद्रमालाध्य
न्याय उगाली के विकल्प के लिए तंत्र को दृढ़
करना चाहिए। विधि आयोग के सुझावों पर
अमल किया तथा अनु० 136 के तहत विशेष अपील
के दुर्लभयोग को रोक जाए।

8. Explain why the Indian Constitution has been argued to have created a 'federation with a centralising tendency'.

ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने 'केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ' को सृजित किया है, व्याख्या कीजिए।

भारत ने संघात्मक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है।

संविधान में संघात्मक विशेषताएं -

- * लिखित व विस्तृत संविधान
- * द्विसदनीय विधायिका - राज्यसभा राज्य के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
- * शक्तियों का विभाजन - सात्वती अनुसूची
- * स्वतंत्र न्यायपालिका
- * विभिन्न आयोग, वित्त आयोग जैसे प्रावधान

एकात्मक विशेषताएं - सैद्धांतिक रूप से संघात्मक विधान है लेकिन व्यावहारिक रूप से केन्द्रीकरण अधिक है।
कारण - ① राज्य धन के लिए केंद्र पर निर्भर - पहले योजना आयोग था तो अधिक निर्भरता थी किंतु अभी भी अनु. 275, 282 आदि
 ② सात्वती अनुसूची के विषयों में केंद्र की शक्ति

में महत्वपूर्ण विषय हैं,
समग्रती सूची के चिह्नों पर केन्द्र का विद्यान
सर्वोपरि है।
पाँच परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी केन्द्र का
बना सकता है।
अवशिष्ट शक्तियाँ भी केन्द्र के पास हैं।

• एकल नागरिकता

* राज्यपाल का पद - विवेकाधीन शक्तियों का
दुरुपयोग देखा जाता है।

* अजिल भारतीय सेवाएं,

• आपातकालीन प्रवधान आदि प्रावधान केन्द्र के अधिक
शक्तिशाली बनाते हैं।

Ex. हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को बिना उनके
विधानमण्डल की सहमति से दो केन्द्र शासित एजेंसियों में
बाँट दिया। यद्यपि यह संवैधानिक उपनिषद् है
(अनुच्छेद 2, 3) किंतु भारत में विनाशी राज्यों का
अविनाशी संघ है। अतः इसे केन्द्रीयकृत करने
का सच कदापि नहीं (आइवर जेनिंग्स)

भारत में समावेशी व पर्याप्त विकास
के लिए सरकारी संघवाद की आवश्यकता है (बुद्धी
आनंद, 2nd ARC)

1391

VISION IAS™

Don't write
anything this
margin
(इस आख में
कुछ ना लिखें)

9. The parliamentary control over government and administration in India is more theoretical than practical. Discuss.

भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण व्यावहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। चर्चा कीजिए।

भारत में शासन के तीन अंगों के
मध्य चेक व बैलेंस की प्रणाली
स्थापित की गई है।

संसदीय नियंत्रण - भारत ने ब्रिटेन की तर्ज पर
उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रणाली पर बल दिया
है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति
उत्तरदायी है क्योंकि अंग्रेज विधायिका ही जनता की आवाज है।

सैद्धांतिक
प्रावधान

- 1. अनुच्छेद 78 - प्रेजिडेंट लोकसभा
के प्रति उत्तरदायी होगी। यह लोकसभा ने विश्वास
तक ही बनी रह सकती है।

2. 105, 194 - संसदीय विशेषाधिकार जो
कार्यपालिका को संसदों को तृटिरहित जवाब
देने के लिए बाध्य करता है।

3. संसदीय नियंत्रण - 1. समितियों द्वारा नियंत्रण

तीन स्थाई समितियाँ - प्रबन्धन

- लोक लेखा

- सार्वजनिक

उपक्रम संस्था

* प्रश्नकाल, शून्यकाल - कार्यपालिका से जनप्रखंड
* विभिन्न प्रस्ताव - विशेषाधिकार, ध्वानाकर्षण, क्वैली
आदि उत्सव

* वित्तीय नियंत्रण - कार्यपालिका संसद की
अनुमति के बिना कोष से नियंत्रण छन
नहीं निकाल सकती हैं (अनु 268, 269)

राज्यीय नियंत्रण - अनुच्छेद 112 आदि

इससे है कि सैद्धान्तिक प्रावधानों
की पूरी बहुत लम्बी है किंतु व्यवहार में
लोफले की अपरिपक्वता, जन जागरूकता की कमी
मीडिया व सिविल सोसाइटी की उमारी
भूमिका की कमी से कार्यपालिका संसद
पर हावी हो जाती है।

ऐसा आम चुनावों में मतदान प्रतिशत व
लोकतन्त्र सीधे की अधिकता से भी देखने
के मिलता है। इससे व्यक्ति पूजा बरही
है। राजनीतिक दल के उमारी लोग ही कार्यपालिका
व विधानिका को नियंत्रित करते हैं इसे
स्वयं व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया
व जागरूक जनता ही संतुलन स्थापित कर सकती हैं।

वर्तमान सरकार में संसदीय नियंत्रण की कमी कई
निम्न उदाहरण साबित आते हैं:-

- * मजबूत विपक्ष की कमी
- * आवश्यक विधेयकों को धन विधेयक के रूप में
रखवाना (आधार अधि० 2018 विवाद)
- * संसद में चर्चा व मतदान के ग्यूनरुप उदाहरण
देखने को मिले हैं।

जनौदेश अपनी जगह सही है किंतु

पाद-विवाद के महत्व को नकारना लोकतंत्र की
परिपक्वता नहीं है। अतः संसद में पारदर्शी व
उत्तरदायीवर्णी तरीके से कार्यपालिका पर निष्क्रियता
जाना चाहिए।

10. Why did the Constituent Assembly replace the original plan to have elected governors in favour of appointment by the President? Also, bring out the arguments that are raised against the current form of appointment of Governors.

संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया? साथ ही, राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीके के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। राज्यों में संवैधानिक उच्च राज्यपाल को बनाया जाता है।

निर्वाचित राज्यपाल क्यों नहीं? -

- * संसदीय शासन में जनता की आवाज ही सर्वोपरि है। अतः मुख्यमंत्री व राज्यपाल दोनों के निर्वाचन से शांति विलास संबंधी समस्या उत्पन्न होती।
- * राज्यपाल का निर्वाचन अनाश्वर्य व खर्चीला भी होगा।
- * राजनीति से जुड़ा राज्यपाल होने पर निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाएगा।
- * ब्रिटेन की संसदीय पद्धति अपने नागरिक कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका का भेद है के वक्त ही भारत ने पद्धति अपनाई।

निम्नलिखित का वर्तमान स्थिति - वर्तमान में राष्ट्रपति केन्द्रीय कैबिनेट के सिफारिश पर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है।

इसके विरुद्ध तर्क - * संघवाद को चोट पहुँचती है

* केन्द्र राज्यपाल का इच्छेपाल स्पेक्ट की नीति फ़ाँटा है Ex. महाराष्ट्र में हाल ही में विवाद

* चुनाव हारने हुए पार्टी नेगटिवो व पक्षपाती सिविल सेवकों को लगाया जाता है

* राजनीतिक भुक्कव बना रहता है

स्पष्ट है कि राज्यपाल का पद सैन्य वी विवाद का विषय रहा है।

सुझाव - राज्यपाल संसदीय व्यवस्था का आवश्यक अंग है अतः इसकी नियुक्ति उठाली व पद को यथास्थिति में रखना चाहिए लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सफ़ा-सफ़ा पर फैसले व सरकारिया आयोग व पूछी आयोग की सिफारिशों को अमल में लाकर आवश्यक पुष्टाएँ किए जाने चाहिए जिनमें निम्न

मुख्य हैं

- * राज्यपाल के त्यागनामों व हस्ताक्षरों के प्रावधान संविधान में उल्लेखित कर कड़े बनाए जाएं बाकि दबाव न रहे।
- * राजनीति इल व निरुद्ध राज्य से संबंध न हो।
- * निरुद्ध कॉलेजिएट की सिफारिश ले हा जिले में CJI, विपक्ष का गेरा शामिल हो जाडि

इनसे राज्यपाल के पद की गरिमा बर्ताई रखी जा सकेगी।

11. Explaining the concept of judicial activism, discuss why it is important for courts not to take over the functions of the legislature or the executive.

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, चर्चा कीजिए कि न्यायालयों के लिए विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों का अतिक्रमण न करना क्यों महत्वपूर्ण है।

न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा आज के बढ़ते जनहितकारी मुद्दों पर फैसले व निर्देश देने की प्रवृत्ति है।

Ex. जनहित याचिका

व्याख्या :- न्यायिक सक्रियता की शुरुआत पीठ बगवती के काल से मानी जाती है जब संविधान की उल्लंघना, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को धरातल पर उतारने के लिए न्यायपालिका ने जनहित के मुद्दों (पर्यावरण, मूलभूत, सम्पदा आदि) को लेकर निर्णय देने शुरू किए। वर्तमान में कुछ विशेषज्ञ इसे अतिप्रतिक्रिया तक पहुँचने का आक्षेप लगाते हैं।

अतिक्रमण न करना क्यों महत्वपूर्ण ?

मांस में शासन के नीचे अंगों को छूट रहा है व बैलेंस की पकड़ के लिए संविधान में लिखा गया है शासन का

किंतु कार्यपालिका व विद्यायिका द्वारा अपनी भूमिका को उजावी रूप से न निभाने पर मूल अधिकारों की रक्षा (अनु० 13, 32, 136, 226) के लिए न्यायपालिका को सक्रियता दिखानी पड़ती है जैसे जीवन के अधिकार (अनु० 21) में स्वच्छ पर्यावरण, अनाज, शुद्ध पानी आदि का अधिकार शामिल करने वाले के लिए निर्देश दिया।

लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वोपरि होती है जिसका प्रतिनिधित्व विद्यायिका करती है अतः विद्यायिका का मुख्य नीति निर्माण व कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है वही कार्यपालिका नीतियों को लागू करती है वही लोकतन्त्र के प्रति जागरूक रूप से उत्तरदायी होती है, कार्य का जवाब देती है अतः इन्हें अपना कार्य करने देना चाहिए अन्यथा न्यायपालिका पर अनपेक्षित कार्यभार पड़ेगा

★ न्यायाधीश जनता से जुड़कर नहीं आते अतः अतिविज्ञान वाले हुए भी नीति निर्माण की शक्ति उन्हें नहीं दी जा सकती है कुछ आलोचकों इस अति सक्रियता को 'अन्सटीयुशन रिसर्दिंग' या 'एडवेंचरिज्म' भी कह रहे हैं जेफाएक बी

अतः न्यायिक सक्रियता से अलिप्तक्रियता में
नहीं' जाना चाहिए अन्यथा 'न्यायाधीशों का
शासन' हो जाएगा जो संसदीय लोकतंत्र
की मूल भावना के विरुद्ध है।

12. Compare the constitutional position of Rajya Sabha with the Lok Sabha in terms of legislative powers. Also bring out special powers given to Rajya Sabha in this context.

विधायी शक्तियों के संदर्भ में लोकसभा के सापेक्ष राज्य सभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में राज्य सभा को दी गई विशेष शक्तियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा
व राज्यसभा (अनुच्छेद 79, 80)

शक्तियों की तुलना

संदर्भ	लोकसभा	राज्यसभा
सामान्य विधेयक	दोनों सदनों के समान शक्तियां होंगी संयुक्त बैठक का उपस्थान।	
वित्त विधेयक	(110) लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को पारित करेगा है जिसे लोकसभा के लगभग एक-तृतीयांश शक्ति	राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। संयुक्त बैठक नहीं
अनुच्छेद 117 (1) (3)		
अनुच्छेद 117 (1) (3)	दोनों सदनों के समान शक्तियां, संयुक्त बैठक नहीं	
अनुच्छेद 117 (1) (3)	अनुदान की मांग केवल लोकसभा ही प्रस्तुत कर सकती है।	प्रस्तुत नहीं कर सकती

राज्यसभा के पास विशेष शक्तियाँ :-

- ① राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है (22)
- ② नयी अपिल भारतीय न्यायाधीशों के चुनन (312) हेतु प्रस्ताव पास कर सकती है।

स्पष्ट है कि विर विधेयक संबंधी

मांगों को छोड़कर राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियाँ रखती है। यद्यपि इसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ भी हैं जो संघवाद के अनुकूल हैं। राज्यसभा की महत्ता को समझकर इसे समान महत्त्व देना चाहिए।

13. Comment upon the distribution of legislative subjects between the Centre and states. Under what circumstances does the Parliament make laws on matters enumerated in the State list?

केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों के वितरण पर टिप्पणी कीजिए। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि बना सकती है?

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। लातरी अनुसूची में केन्द्र व राज्य के मध्य विधायी विषयों का बँटवारा किया गया है।

विधायी विषयों का वितरण -

- संघ सूची में 100, संमक्ती सूची में 52 व राज्य सूची में 61 विषय हैं।
- संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, संचार, बैंकिंग आदि हैं।
- ★ 42^{वाँ} संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के विषयों जैसे शिक्षा आदि वक्की सूची में डाल लिखा गया जहाँ केन्द्र का अधिक नियंत्रण है।
- ★ अवशिष्ट सूची भी केन्द्र के पास है।
- ★ संमक्ती सूची में दोनो के विधान होने पर केन्द्र के विधान को प्राथमिकता दी जाती है।

स्पष्ट है कि विधायी शास्त्रों
का बंटवारा केन्द्र के पक्ष में झुका
हुआ है।

निम्न परिस्थितियों में संसद राज्य सूची
के विषयों पर भी कानून बना
सकती है।

- ① यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से
अनुमति पारित कर दे तो (1 साल तक कार्य)
- ② अंतर्राष्ट्रीय कानून या जेद्दी को लागू
करने हेतु
- ③ यदि दो या अधिक राज्य मिलकर
इस हेतु अनुमति दे दें।
- ④ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में (35A)
- ⑤ राष्ट्रपति शासन की स्थिति में (356)

स्पष्ट है कि विद्यार्थी शक्तियों के क्षेत्र
में केन्द्रीकृत की प्रवृत्ति हैं। घुंघी आप्रोग
व 2nd ARC के सुझावों पर अमल करना
चाहिए।

14. Explain the significance of the concept of 'separation of powers' in a democracy. What can be the reasons for India not following the doctrine in the strict sense?

लोकतंत्र में 'शक्तियों के पृथक्करण' की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत द्वारा इस सिद्धांत का कठोर अर्थों में अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हो सकते हैं?

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था जिसे अमेरिकी संविधान में कठोरता से पालन किया गया है।

महत्व - शासन के तीन अंगों के अपने-अलग कार्य होते हैं। पृथक्करण के अभाव में अतिव्याप्ति व अल्पव्याप्ति हो जाती है।

- * तीनों अंगों के साथ मिल-जुलकर काम करना संभव हो पाता है।
- * न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान व शासक अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक है।
- * विधायिका जनता की आवाज होती है। अतः उन्हें स्वतंत्र नीति निर्माण हेतु पृथक्करण आवश्यक है।

स्पष्ट है कि लोकतंत्र के सफल होने
के लिए शास्त्रि व्यवस्था आवश्यक है।

भारत द्वारा कठोर अनुपालन न करने के कारण :-

- * भारत में बहुत लंबे विलेस शासन उगाती
अपनाई गई है।
- ० भारत में संविधान ही सर्वोच्च है जिसकी
रक्षा न्यायपालिका करती है।
- * भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें
कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है
तथा विधायिका के लिए उत्तरदायी होती है।
- * भारत में मूल अधिकारों की गारंटी भी मूल
अधिकार है अतः न्यायपालिका को न्यायिक
परीक्षण करना पड़ता है।
- * कार्यपालिका की तात्कालिकी को रोककर संसदीय
नियंत्रण अपनाया गया ताकि स्वतंत्रता पूर्ण के
उत्तरदायी अभाव सरकार का अनुभव न
मिले।

स्पष्ट है कि भारत में प्रिय जीवन की व्यवस्था
की निकटता, उत्पादों के जगहों
के स्पष्ट व्यापारिक के लिए नियंत्रण व संरक्षण
पक्षों अपनाने गई जिसे व्यवस्था में भी अधिकतम
साथ रखने के लिए जनता को जागरूक
होना होगा।

15. Explain the grounds on which a National Emergency can be declared and highlight its effects on Centre-state relations and Fundamental Rights.

उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है एवं केंद्र-राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 में उल्लेख है।

आधार - (1) बाह्य - युद्ध या बाह्य आक्रमण होने या होने की संभावना पर

(2) आंतरिक - सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में

इन आधारों पर केन्द्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति संघर्ष राष्ट्र या कुछ हिस्सों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है।

केन्द्र - राज्य संबंधों पर प्रभाव :-

1. राज्यों की कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा विधायिका को विधायित्व या भंग किया जा सकता है।
2. केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर भी कार्य कर सकता है।
3. केन्द्र राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व वितरण को संशोधित कर सकता है।

★ राज्यों के दैनिक विद्येयक को राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकना है

★ राज्य विधानमण्डलों के कार्यकाल बढ़ा जा सकते हैं।

मूल अधिकारों पर प्रभाव :-

अनु० 358

1. अनु० 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जायेंगे

2. संपूर्ण भारत में लागू

3. केवल बाह्य आपातकाल में लागू

अनु० 359

1. अनु० 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति आदेश के निर्धारित समय तक लागू रहेंगे निलंबित रहेगी (गारंटी नहीं मिलेगी)

2. विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है

3. बाह्य व आंतरिक दोनों में लागू

स्पष्ट है कि 358 व 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है जिस पर आपातकाल समाप्ति में भी उल्लंघन नहीं उठाया जा सकता है

16. Analyze how the CAG ensures financial accountability of the Executive to the Legislature while working as an independent Constitutional body.

विश्लेषण कीजिए कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए CAG, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है?

संविधान के अनुच्छेद 148-151 में
CAG के प्रावधान उल्लेखित हैं।

वित्तीय जवाबदेही कैसे सुनिश्चित:-

- * कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिससे वह निम्न होकर कार्यपालिका के व्यय को जांचती है।
- * कैग संसद की तय की गई वित्तीय समिति लोड लेखा समिति का मित्र व पथप्रदर्शक होता है। जिसमें वांछित व्ययों की समीक्षा की जाती है।
- * कैग कार्यपालिका द्वारा लिए गए संसद से व्यय की समीक्षा करता है जो न केवल पारित होता है बल्कि उचित तरीके से खर्च किया गया या नहीं की भी परीक्षा करता है जैसे 20 सेक्टर बोर्ड।
- * कैग अपनी रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाता है जहां कार्यपालिका से विमर्श

प्रश्न पूछ सकते हैं।

- * कैंग की रिपोर्ट के आधार पर मीडिया, प्रिविलेज सोसाइटी व आमजन भी कार्यपालिका पर दबाव बनाते हैं।

स्पष्ट है कि कैंग कार्यपालिका की विलीय जवाबदेही कुनिश्चित ठाके का प्रबल उपकरण है किंतु निम्न बिंदुओं भी हैं -

- * कैंग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर होती है अतः कार्यपालिका अपने परसदीय व्यक्ति को इस पद पर बिठा सकती है।
- * कैंग पर कार्यभार
- * कैंग में लेखाशाला विशेषज्ञों की कमी
- * संसद में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी
- * उदाहरण - शेड्यूल मादले में रिजर्वेटिव डाइरिजिंग ऑडिटर की गरीबी जो प्रश्नचिह्न लगाती है।

निष्कर्ष : कैंग की नियुक्ति कॉलेजियम (CJ2, किपम) से होनी चाहिए। 2nd ARC के सुझाव लागू।

1391

VISION IASTM

Don't write
anything this
margin
(इस भाग में
कुछ ना लिखें)

17. Highlight the veto powers of the President of India. How does the veto powers of the Governor differ from that of the President?

भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों पर प्रकाश डालिए। राज्यपाल की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों से किस प्रकार भिन्न हैं?

अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां का उल्लेख है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां

* जेबी वीटो - राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनन्तकाल तक अपने पास रखा रह सकता है। 19 सितंबर 1960 जैसे जैल सिंह भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में उजोग किया।

* निर्णय वीटो - राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकता है। ऐसा सामान्यतया लोकतन्त्र के विध्वंस पर किया जाता है।

* विशेष वीटो - राष्ट्रपति विधेयक को विधायिका को पुनः लौटा सकता है जिसे विधायिका द्वारा पुनः पास करने पर अनुमति देनी आवश्यक है।

राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत नीचे शक्ति रखता है जो राष्ट्रपति से निम्न अर्थों में निम्न है

राष्ट्रपति (111)

राज्यपाल (200)

- | | |
|--|--|
| <p>1. तीन उकार की वीथी शक्तियाँ हैं</p> <p>2. विधेयक को आगे प्रेजेस का विकल्प नहीं</p> <p>3. विशेष वीथी शक्ति में छुट्टा पुनः लौटा सकतार्व</p> | <p>1. जैवी वीथी शक्ति नहीं है।</p> <p>2. अनु० 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकतार्व</p> <p>3. एक भी वरपुन नहीं लौटा सकतार्व</p> |
|--|--|

रन्यलर है कि रलरूपति की वीथी शक्तियाँ रल्यपाल से विलुत हैं। यह शक्तियाँ विधायिका हलल जलदबाजी में अथवा बिना विधालभर के पारित विधेयको को लैगमित करने के लिए की गइ है।

18. Even though the parliamentary system of government in India is largely based on the British parliamentary model it never became a replica of the British system. Elaborate.

यद्यपि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है तथापि यह कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बनी। सविस्तार वर्णन कीजिए।

भारत में शासन का संसदीय संघात्मक स्वरूप अपनाया गया। जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है।

समानताएँ - 1. ~~प्रधानमंत्री की~~

उच्च सदन व निम्न सदन की
अवधारणा

2. संसदीय विशेषाधिकार

3. नाममात्र कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका में भेद

4. कार्यपालिका का विधायिका में झुका जाना तथा लोकतन्त्र के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व

5. संसद में संशोधन की असीमित शक्ति (यद्यपि भारत में मूल हॉन्स)

6. विधि का शासन
अर्थात्

असमानताएँ

1. ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का निम्न सदन का होना आवश्यक है जबकि भारत में केवल पार्षद
2. भारत में संविधान सर्वोच्च, ब्रिटेन में केवल सर्वोच्च है
3. भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक परीक्षण की शक्ति रखता है, ब्रिटेन में नहीं
4. भारत गणराज्य है।
5. भारत लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है
6. भारत में बड़े कैबिनेट नहीं होती हैं

स्पष्ट है कि ब्रिटेन से व्यवस्था की निकलते होते हुए भी भारत ने इपर्युक्त असमानताएँ अपनाईं जो -

- ① भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल
- ② संघवाद के अनुकूल
- ③ संविधान की जीवंतता के अनुकूल है

अतः भारतीय ^{संविधान} ~~संविधान~~ का डिमें की
प्रतिष्ठा करना डा० अंबेडकर के
गठित संविधान का अपूर्ण अध्ययन
का परिणाम है।

19. A number of judicial pronouncements and constitutional amendments have altered the balance between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy since the commencement of the constitution. Analyse.

संविधान के लागू होने के पश्चात से अनेक न्यायिक निर्णयों और संविधान संशोधनों ने मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के मध्य के संतुलन को परिवर्तित कर दिया है। विश्लेषण कीजिए।

संविधान के भाग 3 (अनु. 12-35) में
मूल अधिकार व भाग 4 (अनु. 36-51) में
नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं।

दोनों के मध्य तुराव सम्पादन
दोराईजान वाद 1951 से ही शुरू हुआ

न्यायिक निर्णय

1. सम्पादन दोराईजान वाद 1951
- मूल अधिकारों को प्राथमिकता

2. गोलाकनाथ वाद 1967
नीति निर्देशक तत्वों को
प्राथमिकता

3. केशवानन्द भारती वाद 1973
मूल हानों का निर्णय

31 वें को मान्यता - 39D, E
के समय अनु. 14 व 19 लागू
नहीं होंगे।

संविधान संशोधन

1. 1st संविधान संशोधन 1951
- नीति निर्देशक तत्वों को
प्राथमिकता

2. 25th CA
समस्त नीति निर्देशक तत्व
मूल अधिकारों पर प्राथमिकता

3. 42nd CA 1976

4. 44th CA 1978
संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार में शामिल किया

५. मिनर्वा मिलस का १९८०, - इसमें 'सर्वोच्च न्यायालय' ने कहा कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं जो दोनों साथ-साथ चलेंगे।

वस्तुतः यह विवाद समाजवादी नीतियों को लागू करने पर संपत्ति के अधिकार का हिस्सा में हुआ। जिसे केशवानन्द भार्गव ने अंग के मान्यता देकर चुलझाया गया।

मूल अधिकार जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक बल देते हैं वहीं DPSP समाज हित का उद्दिष्टित्व करते हैं अतः दोनों के मध्य संतुलन रखा जाना आवश्यक है।

20. Highlight the powers and functions of the Election Commission of India (ECI). Also, discuss the issues regarding the independence and impartiality of the ECI.

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, ECI की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324-329
तक निर्वाचन आयोग संबंधी उल्लेख हैं।

शक्तियाँ व कार्य -

1. भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव [★]
आयोजित करवाना (324) - विश्वव्यापी
हुई है।
2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व आम चुनाव कराना
3. मतदाता सूची तैयार करवाना, प्रधत्न रचना
4. चुनाव सुधार लागू करना - EVM, VVPAT आदि
5. जनप्रतिनिधित्व अधि० 1951 के तहत तपन्यों की
निर्यातन संबंधी राष्ट्रपति की सलाह देना
(अर्धन्यायिक कार्य)
6. राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवेदन
संबंधित विवादों का निपटारा
7. परीक्षण आयोग (एन) प्रद करना तथा चुनाव हेतु
का निर्धारण करना आदि

स्वतंत्रता व निष्पक्षता संबंधी दुई :-

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु
ऐसा ही चुनाव आयोग होना आवश्यक है
जो स्वल्प लोकतंत्र का भी आधार है

- * निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति कॉलेजियल द्वारा
होनी चाहिए क्योंकि इनकी स्वतंत्रता पर कार्यपालिका
का दबाव रहता है
- * अन्य निर्वाचन आयोगों की शक्तियां भी
मुख्य निर्वाचन आयोगों के समान होनी चाहिए
- * सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, डिप्लोम उपायविधि
पुनरा आयोग की सिफारिशें लागू होनी
चाहिए।
- * Ex. चुनावी बॉर्ड के संबंध में निर्वाचन आयोग
के न चाहते हुए भी लागू करना इसकी
संविधानिक को धर्या है

अतः स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के लिए
उपरोक्त सुझावों को लागू किया जाए तथा
चुनाव सुधारों को जल्द अपनाया जाए

